



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937

No. 68]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विटामिन ई के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) के अंतिम जांच परिणाम के संबंध में।

फा. सं. 15/31/2013—डी जी ए डी.-1—जबकि, चीन जन. गण. (इसके बाद संबद्ध देश के रूप में संदर्भित) में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित विटामिन ई (इसके बाद संबद्ध वस्तु के रूप में संदर्भित) के आयातों के संबंध में मूल जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/32/2002—डी जी ए डी के माध्यम से शुरू किया गया था। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 2 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/32/2002—डी जी ए डी के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया गया था और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क 7 मार्च, 2003 को राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2003—सीमा शुल्क द्वारा लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/32/2002—डी जी ए डी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना निश्चित शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए जारी की गई थी, जिसका अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, एक निश्चित पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 6 अक्टूबर, 2003 के अधिसूचना संख्या 145/2003—सीमा शुल्क के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था।

- जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी (डी ए) ने दिनांक 7 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/10/2008 - डी जी ए डी के माध्यम से प्रथम अंतिम जांच परिणाम शुरू किया था। उक्त प्रथम अंतिम जांच परिणाम के संबंध में अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/10/2008—डी जी ए डी के माध्यम से जारी की गयी थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई इस सिफारिश के आधार पर एक निश्चित पाटनरोधी शुल्क दिनांक 27 मार्च, 2009 की

अधिसूचना संख्या 33/2009-सीमा शुल्क के तहत केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी बनाया गया।

3. जबकि, मर्क लिमिटेड ने शुल्क को वापिस लिये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली हानि का आरोप लगाते हुए इस अधिनियम और नियमावली के अनुरूप प्राधिकारी के समक्ष के विधिवत सिद्ध आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने अथवा उसे बढ़ाने के लिए अंतिम समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग की ओर से दायर किये गये विधिवत सिद्ध आवेदन को देखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ कथित इस अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुरूप प्राधिकारी ने संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को लगातार लगाने के लिए आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से संभवतः पाटन जारी रह सकता है अथवा बार-बार हो सकता है और इससे घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है, के लिए दिनांक 24 मार्च, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से दूसरी अंतिम समीक्षा जांच शुरू की। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैद्यता केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 9 मई, 2014 के अधिसूचना संख्या 16/2014-सीमा शुल्क (पाटनरोधी शुल्क) के माध्यम से 26 मार्च, 2015 तक बढ़ायी गयी थी।

क. प्रक्रिया

4. नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :
 - क) नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावास को सीमा शुल्क नियमावली, 1995 के नियम 6(2) के अनुरूप इन जांचों को शुरू करने के संबंध में सूचित किया गया।
 - ख) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुरूप संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात निर्यातकों को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराईं। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भी सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध करायी गयी थी और इसे जहां भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया था।
 - ग) प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके नाम व पते इस प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें नियमावली 6(2) और 6(4) के अनुरूप पत्र की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का अवसर दिया :
 - (i) मैसर्स ज़ेज़िंग नहू कम्पनी लिमिटेड, चीन
 - (ii) मैसर्स ज़ेज़ियांग एक्सइनचांग फारमासिटिकल कम्पनी, चीन
 - (iii) मैसर्स हांगजूड तोयांड बायोटेक कम्पनी, लिमिटेड, चीन
 - (iv) मैसर्स वेगा फार्मा लिमिटेड, चीन
 - (v) मैसर्स एक्सिएन रेनबो बायोटेक, कम्पनी लिमिटेड, चीन
 - (vi) मैसर्स क्विंगडओ सुनराइस ट्रेनिंग कम्पनी लिमिटेड, चीन
 - (vii) मैसर्स अनहूई मेडीफार्म कम्पनी, लिमिटेड, चीन
 - घ) संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों में से किसी भी उत्पादक और निर्यातक द्वारा कोई उत्तर अथवा अनुरोध दायर नहीं किया गया है।
 - ङ) एक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एम ई टी) प्रश्नावली भी चीन जन. गण. के दूतावास और ज्ञात सभी उत्पादकों/निर्यातकों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की गई थी कि वे इस प्राधिकारी को संबंधित सूचना निर्धारित समय के भीतर प्रदान करें। जबकि जांच शुरू करने के प्रयोजन से, चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य पर विचार भारत में विधिवत समायोजित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया था, फिर भी प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया कि इसने यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में आवेदक के दावे की जांच करने का निश्चय किया है। अतः चीन जन. गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि वे इस प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने में कि बाजार अर्थव्यवस्था वर्तव सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को ही दिया जा सकता है, समक्ष बनाने के लिए पैरा 8 के उप पैरा (3) में यथा-उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें। हालांकि, इस संबंध में चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

- च) प्राधिकारी ने भारत के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनका नाम व पत प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया था) को आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें नियमावली 6(4) के अनुरूप पत्र के जारी होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का अवसर दिया :
- (i) मैसर्स सी. जे. शाह एंड कम्पनी, मुम्बई
 - (ii) मैसर्स काडिला फार्मासिटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
 - (iii) ग्लेनमार्क फार्मासिटिकल्स लिमिटेड, मुम्बई
 - (iv) मेदी फार्मा ड्रग हाउस, मुम्बई
 - (v) नंदलाल बंकतलाल प्रा. लिमि., मुम्बई
 - (vi) नव महाराष्ट्रा चकन ऑयल मिल्स, पुणे
 - (vii) मैसर्स शीतल फार्मा, मुम्बई
 - (viii) सुंदर केमिकल्स प्रा. लिमि., चैन्नई
 - (ix) यूनिवर्सल मेडिकेयर प्रा. लिमि., मुम्बई
- छ) किसी आयातक/प्रयोक्ता/हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई उत्तर/अनुरोध दायर नहीं किया गया।
- ज) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन से जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 थी। हानि के विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में जनवरी-दिसंबर 2010, जनवरी-दिसंबर 2011, जनवरी-दिसंबर 2012 और जांच की अवधि शामिल थी।
- झ) घरेलू उद्योग ने दूसरे स्रोतों अर्थात् आई बी आई एस से प्राप्त आंकड़ों पर विश्वास किया था। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से जांच की अवधि और जांच के अवधि के बाद की अवधि को शामिल करते हुए हानि की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के व्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि, जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा आई बी आई एस स्रोत के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक है अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में आई बी आई एस स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ञ) निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस जांच से संबंधित सूचना न तो दी है और न ही प्राधिकारी को कोई उत्तर दिया है, को इस प्राधिकारी द्वारा गैर-सहयोगी पक्षकार के रूप में माना गया है।
- ट) प्राधिकारी ने सीमा-शुल्क नियमावली, 1995 के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया था।
- ठ) प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना को भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर यथा-संभव जांच की है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली हानि से बचाने के लिए पर्याप्त होगा।
- ड) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुरूप, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 9 जनवरी, 2015 को आयोजित आम सुनवाई जिसमें घरेलू उद्योग और उनके प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए थे, में मौखिक रूप से अपने विचार रखने का अवसर भी दिया। घरेलू उद्योग जिसने मौखिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने दृष्टिकोण को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
- ढ) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में विचार किया गया और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करें।

ण) ***इस अंतिम जांच परिणाम में गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा ऐसा माने जाने को इंगित करता है।

त) पी ओ आई के लिए विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा 58.95 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र

5. पूर्व की जांचों तथा वर्तमान अंतिम समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) चीन जन. गण. में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित (प्राकृतिक रूपों को छोड़कर सभी रूपों में विटामिन-ई) है। वर्तमान जांच दूसरा अंतिम जांच परिणाम है अतः इस जांच में मूल और परिणामी अंतिम समीक्षा जांच में उत्पाद शामिल है। विटामिन ई एसीटेट विटामिन ई का स्थायी रूप है जिसका अधिकतम उपयोग इसकी स्कीन केयर लाभों के लिए कॉस्मेटिक के निर्माण में किया जाता है। विटामिन ई सैल मेम्बरेन्स को नष्ट होने से ऑक्सीजन मुक्त रेडिकल्स के द्वारा बचाता है। यह यूवी रेडियेशन और लिपिड पैरोक्सीडेशन से प्रभावित होने वाले चमड़े के समय के पूर्व शिथिल होने से बचाता है। जबकि, विटामिन ई फीड ग्रेड का उपयोग जानवरों के चारे के निर्माण में किया जाता है।
6. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा यथा-परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के अर्थ और क्षेत्र का विरोध नहीं किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयात किये गये वस्तुओं के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के सीमा शुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं। इसके अलावा यह नोट किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पिछली दो जांचों में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के जारी होने की जांच की है जिस पर विश्वास किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य हैं।
7. उत्पाद, विटामिन ई-एसीटेट का वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम का सीमा शुल्क वर्गीकरण 2936 28 00 के अंतर्गत अध्याय 29 में किया गया है जबकि विटामिन ई (50 प्रतिशत सूखा पाउडर) फीड ग्रेड का वर्गीकरण सीमा शुल्क वर्गीकरण 2309 90 10 के अंतर्गत अध्याय 23 में किया गया है। हालांकि, उपर्युक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग और उसका स्थान

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

8. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - (i) यह याचिका मैसर्स मर्क लिमि. द्वारा दायर की गई है। एक अन्य कम्पनी मैसर्स सोहम ऑर्गेनिक लिमि., नासिक भी इस उत्पाद का उत्पादन करता है। अन्य विनिर्माता की इस याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है यद्यपि उन्होंने इस आशय का कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
 - (ii) जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन में 84 प्रतिशत हिस्सा है और इस कारण से यह घरेलू उद्योग है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और उसका स्थान निर्णायक समीक्षा में संगत नहीं है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

9. किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स मर्क लिमि. द्वारा आवेदन दायर किया गया है।
11. इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सोहम ऑर्गेनिक भी इस उत्पाद का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मैसर्स मर्क लिमि. का जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन में 84 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक का उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है और इस कारण से आवेदक घरेलू उद्योग है। इसके अलावा घरेलू उद्योग के स्थान एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में वर्तमान जांच में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना और नियमावली पर विचार करते हुए प्राधिकारी इस तथ्य को मानता है कि मैसर्स मर्क लिमि. का संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह नियमावली के अर्थ की दृष्टि से घरेलू उद्योग है और इसका नियमावली के अंतर्गत स्थान है।

घ. बाजार अर्थव्यवस्था वर्ताव, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन-पद्धति, मानदण्ड और पाटन के जारी रखने की संभावना का निर्धारण

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

12. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- I. चूंकि किसी भी चीनी कम्पनी द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है अतः संबद्ध देश को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।
- II. पूर्व के निर्णायक समीक्षा जांचों में, प्राधिकारी ने चीन के किसी भी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था वर्ताव नहीं मंजूर किया था और इसने यथासंशोधित उप-नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के मामले में उचित लाभ के साथ चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर तय किए गए सामान्य मूल्य के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था। प्राधिकारी को वर्तमान जांच में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए उसी पद्धति पर विचार करना चाहिए।
- III. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में मूल्य और (ख) विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन की लागत जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और लाभ शामिल किया गया हो, के आधार पर किया जा सकता है। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- IV. याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच में भी चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने हेतु उसी पद्धति पर विचार करने का दावा किया है क्योंकि चीन के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने जांच शुरू करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है।
- V. याचिकाकर्ता ने भारत में संबद्ध आयात की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए आई बी आई एस आंकड़ों पर विचार किया है। हालांकि भारतीय सीमा शुल्क को सूचित किया गया मूल्य अविश्वसनीय है। यह इस बात से सिद्ध हो गया है कि जिस मूल्य पर विटामिन ई का निर्यात चीन से पूरे विश्व में किया गया है वह उस मूल्य से बहुत कम है, जिस पर भारत को उस वस्तु का निर्यात किया गया है। जिस मूल्य पर इन वस्तुओं की सूचना भारतीय सीमा शुल्क को दी गई है वह भारत में इस उत्पाद के लिए प्रचलित मानक मूल्य पर है। जिस मूल्य पर आयात किए गए वस्तुओं को भारत में पुनः बेचा गया है जैसा कि उस उत्पाद के पुनः बिक्री मूल्य से स्पष्ट होता है वह बहुत कम है।
- VI. उपर्युक्त को देखते हुए, याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वह भारतीय सीमा शुल्क को सूचित किए गए मूल्यों को दरकिनार करें और आयात मूल्य तय करने के लिए इस उत्पाद की पुनः बिक्री मूल्य पर विचार करें। याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे कृपया इस नियम के अंतर्गत निर्यात मूल्य की परिभाषा पर विचार करें। वर्तमान मामले में चूंकि मूल्य जिस पर वस्तुओं का निर्यात किया गया है अविश्वसनीय है। अतः निर्यात मूल्य भारत में पुनः बिक्री मूल्य से तय किये जाने की आवश्यकता है।
- VII. चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार चीन से देशवार निर्यात के आधार पर पाटन और क्षति के मार्जिन की गणना से यह देखा जा सकता है कि चीन से तीसरे देशों को निर्यात पाटन मूल्य पर किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि अधिकतर देशों के मामले में पाटन का मार्जिन और हानि का मार्जिन बहुत अधिक है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

13. किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

बाजार अर्थव्यवस्था के दावे की जांच

14. जांच आरंभ करने के चरण में प्राधिकारी ने एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में चीन जन. गण. को मानकर इस पूर्वानुमान के साथ कार्यवाही शुरू की। जांच आरंभ करने पर प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच आरंभ करने की सूचना का उत्तर देने और अपने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण करने से संबंधित सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की कल्पना का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एम ई टी प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन सरकार से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए अपने देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह देने का भी अनुरोध किया। हालांकि किसी चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन. गण. को भारत और डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश को वर्तमान जांच में गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानते हैं।

सामान्य मूल्य का निर्धारण

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी द्वारा जारी जांच आरंभ करने संबंधी सूचना के परिणामस्वरूप उन्होंने गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का भी खंडन नहीं किया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और प्रतिवादी चीनी कम्पनी द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन न किए जाने पर प्राधिकारी इसे चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नावली के अनुबंध के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने को उचित समझता है।
16. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में निम्नलिखित उपबंध है कि:
 “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रशस्त उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”
17. संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इस प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और न ही वर्तमान जांच का उत्तर दिया है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली में यथा परिभाषित किसी अन्य वैकल्पिक आधार जिस पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है, प्रदान किया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार करते हुए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध के पैरा 7 के अनुरूप सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध के पैरा 7 में यथा निर्धारित अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकार्ड पर उपलब्ध पर्याप्त सूचना के न होने के कारण प्राधिकारी ने ‘अन्य उचित आधार’ की पद्धति को अपना कर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। अतः प्राधिकारी ने भारत में आवेदक घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य तय किया है। प्राधिकारी ने अपनी सतत प्रथा के अनुसार उचित लाभ का भी प्रावधान किया है। तदनुसार, यथा निर्धारित चीनी निर्यातकों के लिए प्रस्तावित तय की गई सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन के लिए नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

निर्यात मूल्य

18. संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है जिसका उपयोग निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय सीमा शुल्क के प्रविष्टि बिल में घोषित मूल्य इस उत्पाद पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के मानक रूप के कारण अविश्वसनीय है। वे ऐसा आरोप इन आधारों पर लगा रहे हैं कि जिस मूल्य पर विटामिन ई का निर्यात चीन से शेष विश्व में किया गया है वह उस मूल्य से बहुत कम है जिस पर वस्तुओं का निर्यात भारत को किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात पूर्व के पाटनरोधी शुल्क की अधिसूचना में यथा अधिसूचित इस उत्पाद के लिए लगभग मौजूदा मानक मूल्य पर किया गया है। आवेदक ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के संबंध में एक पुनः बिक्री बीजक प्रस्तुत किया है जिसमें मूल्य आयात मूल्य की तुलना में कम है जिससे उनके इस दावे को समर्थन मिल रहा है कि सीमा शुल्क को घोषित किया गया मूल्य सही नहीं है और यह पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना के अंतर्गत सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए है।
19. प्राधिकारी ने इन अनुरोधों को पढ़ा है। आवेदक ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए एकमात्र पुनः बिक्री बीजक दिया है, प्राधिकारी भारत में सूचित किए गए पुनः बिक्री मूल्य के आधार पर निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसे उपयुक्त समझते हैं साथ ही ये वस्तु भारत में लगभग उसी मूल्य पर सभी देशों से आ रही है। चीन के किसी भी निर्यातक ने इस प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और इस कारण से प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर निर्यात मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी ने आई वी आई एस के आयात संबंधित सूचना के आधार पर चीन जन. गण. के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है। ये मूल्य भारत को सी आई एफ निर्यात मूल्य हैं। सी आई एफ मूल्य से समायोजन रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, निर्यात मूल्य का समायोजन कमीशन, पतन शुल्क, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय और समुद्री माल भाड़ा और समुद्री बीमा के लिए किया गया है। प्राधिकारी द्वारा तय किया गया निवल निर्यात मूल्य पाटन मार्जिन के लिए नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

पाटन मार्जिन

20. ऊपर में निर्धारित किए गए अनुसार एक्स फैक्ट्री स्तर पर निर्यात मूल्य के साथ तय किये गये सामान्य मूल्य की तुलना करने पर, संबद्ध देश में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :-

सामान्य मूल्य	अमरीकी डॉलर/प्रति किलोग्राम	***
निबल निर्यात मूल्य	अमरीकी डॉलर/प्रति किलोग्राम	***
पाटन मार्जिन	अमरीकी डॉलर/प्रति किलोग्राम	***
पाटन मार्जिन प्रतिशत	%	***
पाटन मार्जिन रेंज	%	5-15

ड. हानि के निर्धारण के लिए पद्धति और हानि एवं कारणात्मक संबंध की जांच

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

21. घरेलू उद्योग ने हानि और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- I. चीन से विचाराधीन उत्पाद का लगातार पाटन हो रहा है।
- II. यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो विचाराधीन उत्पाद का पाटन संबद्ध देश से और अधिक होने की संभावना है।
- III. पाटित आयातों की मात्रा वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद बढ़ी है।
- IV. मूल्य में कटौती बहुत अधिक सकारात्मक है। इसके अलावा चीनी निर्यातक बहुत अधिक मात्रा में इस उत्पाद का पाटन विभिन्न अन्य देशों में कर रहे हैं जैसा कि प्रमुख आयातक देशों के लिए निर्धारित मूल्य कटौती से स्पष्ट है।
- V. लाभ, निवेश पर आय, माल सूची आदि के मामले में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन जांच की वर्तमान अवधि में और अधिक खराब हो गई है।
- VI. यद्यपि उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग के कारण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार आया है फिर भी घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के बावजूद स्पष्ट रूप से अपेक्षा से कम था जैसा कि घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग विगत स्तरों और जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को स्थगित करने से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।
- VII. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग के मूल्य के मानदंडों में गिरावट आई है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जायेगा तब घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री आयात मूल्य से तुलनीय मूल्य पर करने पर बाध्य होगा। इसका मतलब यह है कि इस उद्योग को बहुत अधिक वित्तीय घाटा, निवेश पर नकारात्मक लाभ और बहुत अधिक नकद घाटे होंगे।
- VIII. निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हानि पाटित आयात से हुई है और उससे कारणात्मक संबंध स्थापित होता है :
 - क) संबद्ध देश से पाटित आयात भारतीय पोर्ट में जांच की अवधि में लगातार प्रवेश किया है।
 - ख) संबद्ध आयात घरेलू मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। जैसे ही पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है, पाटित आयात से और अधिक हानि होगी।
 - ग) विचाराधीन उत्पाद का आयात जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है।
 - घ) चीनी उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं और उनका निर्यात अभिमुखीकरण यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाये तो पाटित आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होगी।
 - ड) ये आयात इस देश में कम और पाटित मूल्य पर प्रवेश कर रहे हैं और ये घरेलू उद्योग के मूल्य में कटौती कर रहे हैं। इस कारण से घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क के बंद होने की स्थिति में मूल्यों में कटौती करने के लिए बाध्य होगा।
 - च) ये आयात घरेलू मूल्य में कटौती कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को बाजार में मूल्य में कमी का सामना पहले से ही करना पड़ रहा है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे हुए हैं जो पाटनरोधी शुल्क के बंद होने की स्थिति में और अधिक बढ़ेगा।
 - छ) घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन मूल्य में कमी के फलस्वरूप लाभ, निवेश पर आय और नगदी का प्रवाह जैसे मानदंडों के मामले में और अधिक गिरा है।
 - ज) किसी पाटनरोधी उपाय के न किए जाने की स्थिति में, पाटन और हानि के जारी रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

- झ) चीन से सभी तीसरे देशों जिसे चीन ने निर्यात किया है, से निर्यात के मामले में पाटन और हानि मार्जिन जिसमें भारित औसत निर्यात मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन और हानि मार्जिन की गणना दर्शाता है कि अधिकतर देशों के मामले में पाटन मार्जिन और हानि मार्जिन बहुत अधिक हैं।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

22. किसी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग को हानि के संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी संबद्ध देश से आयात के कारण पाटन और हानि के पहलुओं की संभावना की जांच करने के लिए कार्यवाही के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान हानि, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।
24. अनुबंध ॥ के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति जांच में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए...” ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
25. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की हालत पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध ॥ के अनुसार विचार किया गया है।
26. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि उसे पहले समाप्त नहीं किया गया हो, इसके लगाये जाने की तारीख से 5 वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जायेगा बतर्श कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से संभवतः पाटन और हानि जारी रहेगी अथवा वह बार-बार होगा, यह समय समय पर 5 वर्षों की एक अतिरिक्त अवधि के लिए इस शुल्क को लगाने की अवधि में विस्तार कर सकता है और आगे की यह अवधि इसके विस्तार के आदेश की तिथि से शुरू होगी।
27. वर्तमान जांच के विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों का मूल्य और मात्रा के प्रभावों और पाटन तथा हानि के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो तथा हानि की मौजूदगी की जांच करने के लिए मूल्य और लाभप्रदता पर इसके प्रभावों की जांच की है। प्राधिकारी ने मैसर्स मर्क लिमि. जो नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग है, के संबंध में सूचना पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को होने वाली हानि की जांच की है। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य पर प्रभाव की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

मात्रा का प्रभाव

पाटित आयातों की मात्रा का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग और बाजार का हिस्सा

28. मांग और बाजार के हिस्से का विश्लेषण नीचे दिये गये के अनुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
आकलित मांग	मी. ट.	837	980	1,071	1,377
घरेलू उद्योग की बिक्री (आबद्ध खपत सहित)	मी. ट.	316	370	438	461
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	100	100	100	100

आयात—चीन जन. गण.	मी. ट.	49	105	243	253
आयात—अन्य देश	मी. ट.	372	405	289	562
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	38	38	41	34
अन्य भारतीय उत्पादक	%	12	10	9	7
संबद्ध देश - आयात	%	6	11	23	18
अन्य देश—आयात	%	44	41	27	41

29. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री (अन्य उत्पादक की बिक्री याचिकाकर्ता द्वारा एक अनुमानित आंकड़ा है) और आई बी आई एस से यथा उपलब्ध सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में देश में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत का निर्धारण किया है। याचिकाकर्ता ने चीन के सीमा-शुल्क के अनुसार चीन से भारत को निर्यात के आधार पर विचार किए जाने के लिए चीन से आयात की मात्रा जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का दावा किया है। हालांकि प्राधिकारी ने आई बी आई एस के आयात के आंकड़ों के आधार पर हानि के विश्लेषण के आंकड़ों पर विचार किया है। इसके आधार पर मांग का आकलन किया गया है, जिसका उल्लेख उपर्युक्त तालिका में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान देश में उत्पाद की मांग में आधार वर्ष तथा उसके ठीक पहले के वर्ष को देखते हुए वृद्धि हुई है।
30. इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और उसके ठीक पहले के वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कम हुआ है। इसके विपरीत संबद्ध देश से आयात का हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है।

आयात मूल्य एवं बाजार हिस्सा

31. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि पूर्ण रूप में अथवा उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष हुई है।

विवरण	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
संबद्ध देश	मी. ट.	49	105	243	253
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	212	493	513
अन्य देश	मी. ट.	372	405	289	562
प्रवृत्ति		100	109	78	151
कुल आयात	मी. ट.	421	510	533	816
मांग	मी. ट.	837	980	1071	1377
घरेलू उत्पादन	मी. ट.	360	426	466	508
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयातों का बाजार का हिस्सा					
कुल आयात	%	12%	21%	46%	31%
मांग	%	6%	11%	23%	18%
घरेलू उत्पादन	%	14%	25%	52%	50%

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आधार पर संबद्ध देश से आयात की मात्रा पूर्ण रूप में अधिक है। इसके अलावा, घरेलू मांग और उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयात भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है।

मूल्य का प्रभाव

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

33. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यों पर प्रभाव की जांच मूल्य में कटौती, कम मूल्य पर बिक्री, मूल्य पर दबाव और मूल्य के रुकावट के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री की प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित मूल्य (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से आयात के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की एक तुलना पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री मूल्य के बीच की गई थी। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में करें, छूट, बट्टे और कमीशन जिसका भुगतान घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है, का समायोजन किया गया है। कम मूल्य पर बिक्री हानि के आकलन का एक प्रमुख सांकेतिक है और इस प्रकार प्राधिकारी ने क्षति रहित मूल्य तय किया है और उसकी तुलना कम मूल्य पर बिक्री की सीमा तय करने के लिए पहुंच मूल्य के साथ की गई है। क्षतिरहित मूल्य का मूल्यांकन घरेलू उद्योग के लिए जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत पर उपयुक्त रूप से विचार करते हुए नियमावली के अनुबंध 111 में निर्धारित सिद्धांतों के मामले में घरेलू उद्योग के लिए किया गया है। संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य पर विचार आई बी आई एस आयात के आंकड़ों के आधार पर निर्यात मूल्य के आधार पर किया गया है। स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2010	2011	2012	2013
आयात की मात्रा	मी. ट.	49	105	243	253
आयात का मूल्य	लाख रु. में	736	1419	3439	3596
आयात की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	1,591	1,444	1,508	1,514
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत (औसत)	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती का रेंज	%	10-20	0-10	0-10	(0-10)

34. उपर्युक्त तालिका से नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है यद्यपि पिछले वर्षों में कीमत में कटौती सकारात्मक थी। आवेदक ने दावा किया है कि चीन से तीसरे देशों को निर्यात मूल्य में बहुत अधिक कटौती और भारित औसत आधार पर कीमत में कटौती तथा अधिकतर तीसरे देशों में ऐसा किया जाना दर्शाता है। आवेदक ने उस मूल्य पर विचार करते हुए सूचित किए गए कीमत की कटौती और कम कीमत पर बिक्री का ब्यौरा प्रदान किया है जिस पर सामानों का निर्यात चीन द्वारा विभिन्न तीसरे देशों को किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्य की कटौती और कम कीमत पर बिक्री दोनों अनेक देशों के मामले में और भारित औसत आधार पर बहुत अधिक हैं।

कम कीमत पर बिक्री

विवरण	इकाई	पी ओ आई
क्षतिरहित मूल्य	रु./किग्रा.	***
पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	1,514
कम कीमत पर बिक्री	रु./किग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री का रेंज	%	0-10

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है जिसके फलस्वरूप कम कीमत पर बिक्री होती है।

कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण

36. घरेलू मूल्य पर पाटित आयातों के मूल्य पर दबाव और रुकावट संबंधी प्रभावों की जांच करने के लिए, घरेलू उद्योग का निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति की तुलना बिक्री की लागत से की गई है। नीचे दी गई तालिका में आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 2011 में कम हुई है, 2012 में उसी स्तर पर रही और तब जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि इसमें हुई है। दूसरी ओर बिक्री कीमत जांच की अवधि के दौरान कम हुई है जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को बहुत अधिक घाटा हुआ है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग मूल्य पर दबाव और संबद्ध देश से पाटित आयातों के रुकावट संबंधी प्रभावों से प्रभावित हुई थी।

विवरण	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	97	120
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	83	80
आयात की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	95	95

घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानदण्डों की जांच

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित वस्तुओं के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन तथा बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार का हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन के आकार में वास्तविक और संभावित गिरावट, नकदी के प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश प्राप्त करने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों वाले सूचकांक शामिल किए जाने चाहिए। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच यह उजागर करती है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

बिक्री, क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और माल सूची

38. प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका से नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री की मात्रा जांच की अवधि में बढ़ी है। क्षमता के उपयोग में भी आउट सोसर्सिंग के कारण उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप सुधार आया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि क्षमता का अभी भी कम उपयोग किया गया है। इस तथ्य के बावजूद ऐसा है कि देश में मांग याचिकाकर्ता की क्षमता की तुलना में बहुत अधिक है। आगे याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे माल सूची में बहुत अधिक वृद्धि के कारण जांच की अवधि के बाद की अवधि में उत्पादन में कटौती करने और उसे स्थगित करने के लिए बाध्य थे। यह दर्शाता है कि घरेलू बिक्री में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई है जिससे भंडार में वृद्धि हो रही है।

विवरण	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
क्षमता	मी. ट.	600	600	600	600
उत्पादन	मी. ट.	360	426	466	508
क्षमता का	%	60	71	78	85
घरेलू बिक्री	मी. ट.	175	242	273	326
आवृद्ध	मी. ट.	141	129	165	135
औसत माल	मी. ट.	16	12	7	32

लाभ/घाटा, निवेश पर आय और नकदी का प्रवाह

39. निवेश पर आय, व्याज पूर्व और व्याज बाद लाभ/हानि तथा नकद लाभ नीचे तालिका में दर्शाये गए हैं :

विवरण	इकाई	201	201	201	पीओ
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	97	120
बिक्री मूल्य	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	83	80
लाभ/घाटा	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	37	40	-43
लाभ/घाटा (कुल)	रु. लाख	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	62	-81
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीब	100		65	-75
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विक्री की लागत में 2011 में गिरावट आई है, 2012 में उसी स्तर पर रहा है और फिर जांच की अवधि में इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा उल्लेख की गई लागत में वृद्धि का कारण यह है कि एक कच्चे माल नामतः इसो फाइटोल के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। हालांकि विक्री के मूल्य में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को बहुत अधिक घाटा हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान घाटा उठाना पड़ा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयात से घरेलू कीमत पर दबाव पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

बाजार का हिस्सा

41. नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गये आंकड़े बताते हैं कि घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश से आयात के बाजार हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
घरेलू उद्योग	%	38	38	41	34
अन्य भारतीय उत्पादक	%	12	10	9	7
संबद्ध देश- आयात	%	6	11	23	18
अन्य देश-आयात	%	44	41	27	41

रोजगार एवं मजदूरी

42. नीचे दी गई तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार और मजदूरी दोनों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथापि यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के बहु उत्पादक कंपनी होने के कारण, ये मानदंड वर्तमान और संभावित प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शा सकते हैं।

विवरण	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	174	211
मजदूरी	लाख रु. में	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	102	159

उत्पादकता

43. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता आधार वर्ष की तुलना में बढ़ी है हालांकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता की गिरावट को दर्शाती है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह भी बड़े हुए लागतों के कारणों में से एक हो सकता है।

विवरण	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
उत्पादकता प्रतिदिन	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	130	141
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	74	67

पाटन मार्जिन का आकार

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

वृद्धि

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने कुछ आर्थिक मानदंडों जैसे उत्पादन और घरेलू बिक्री में सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। हालांकि मूल्य मानदंडों जैसे लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

विकास वर्ष दर वर्ष	इकाई	2010	2011	2012	पी ओ आई
उत्पादन	%	-	18.07	9.53	8.91
बिक्री की मात्रा	%	-	37.81	13.06	19.42
उत्पादन की लागत	%	-	-2.59	0.06	23.64
बिक्री कीमत	%	-	-17.55	0.87	-3.85
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-55	9	-230

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

46. चूंकि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है अतः पूंजीगत निवेश जुटाने की इसकी क्षमता संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

च. कारणात्मक संबंध

47. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को हानि हो सकती थी।

- I. **तीसरे देशों से आयात** : प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि तीसरे देशों से आयात उस मूल्य पर हुआ है जो चीन से आयात मूल्य से थोड़ा अधिक है। यह दावा किया गया है कि तीसरे देशों से निर्यातकों को चीनी निर्यातकों द्वारा दिए जा रहे मूल्यों पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि दावा की गई हानि तीसरे देशों से आयात के कारण भी हो सकते हैं।
- II. **मांग में कमी** : प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि इस देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि के दौरान सतत वृद्धि हुई है।
- III. **खपत की पद्धति** : यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की खपत की पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन प्राधिकारी के ध्यान में नहीं आया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है।
- IV. **प्रतिस्पर्धा की स्थिति** : प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं घरेलू उद्योग को दावा की गई हानि के लिए जिम्मेदार हैं।
- V. **प्राधिकरण का विकास** : प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह भी नोट करते हैं कि जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण दावा की गई हानि हो सकती है।
- VI. **घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन** : घरेलू उद्योग के निर्यातकारी निष्पादन प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि घरेलू उद्योग का मूल्य और लाभप्रदता को प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को हानि का आकलन करने के प्रयोजन से घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए अलग अलग रखा गया है।

छ. पाटन और हानि की संभावना**घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

48. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- I. संबद्ध देश में निर्यातकों के पास भारतीय मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं। पाटनरोधी शुल्क को निरस्त करने की स्थिति में, संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और अधिक बढ़ना तय है।
- II. चीन के कुछ उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है जबकि इस देश में उत्पादन की वास्तविक क्षमता 55000 से 60000 मि. ट. प्रति वर्ष (ऑन लाइन स्रोतों से प्राप्त) तक हो सकती है :

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता (मी. टन)
1	हांगझोउ टॉयड बायोटेक लिमि.	15,000–40,000
2	झिझियांग मेडिसन कम्पनी लिमि.	20,000

- III. चीन जन. गण. के निर्यातकों का पूरे विश्व में बहुत अधिक निर्यात उन्मुखीकरण है। चीन की कम्पनियों का निर्यात का प्रतिशत 81-100 प्रतिशत तक है (ऑन लाइन स्रोतों से प्राप्त)।

उत्पादक/निर्यातक	निर्यात उन्मुखीकरण
वेगा फार्मा लिमिटेड	81%–90%
एक्सियन रेनबो बायोटेक कम्पनी लिमि.	81% - 90%
किंगड्यो सनराइज ट्रेडिंग कम्पनी लिमि.	91% - 100%
अनहुई मेडिफार्म कम्पनी लिमि.	91% - 100%

- IV. चीन में विचाराधीन उत्पाद विटामिन ई का उत्पादन करने वाले अधिकांश उत्पादक राज्य के स्वामित्व में/राज्य के नियंत्रण वाले उपक्रम हैं। चीन की सरकार का शहरों में बड़ा स्टेक है और वे प्रबंधन का नियंत्रण करते हैं। इस कारण से इन कम्पनियों का उद्देश्य किसी तरह से व्यापार प्राप्त करना होता है और न कि वह मूल्य जिस पर वे उत्पाद को बेचेंगे। यह देखा जायेगा कि चीन से विचाराधीन उत्पाद का लगभग 80 प्रतिशत निर्यात राज्य के स्वामित्व वाले नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है।
- V. पिछली दो जांचों में पाटन मार्जिन बहुत अधिक था।
- VI. घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद भी आदर्शत्मक स्तर से कम था।
- VII. संबद्ध देश से आयात पाटनरोधी शुल्क के न रहने पर भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के मूल्यों में कटौती करेंगे।
- VIII. आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और विक्री मूल्य से बहुत कम है। इस प्रकार वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के हटा लिये जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात मूल्य पर बेचने का विकल्प अपनाता है तब घरेलू उद्योग को बहुत अधिक वित्तीय घाटे उठाने पड़ेंगे।
- IX. संबद्ध देश से निर्यातकों और उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क के लगाने के बाद भी पाटित मूल्य पर सामग्री का निर्यात करना जारी रखा है। इस बात पर विचार करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान मामले में शुल्क को निरस्त करने के फलस्वरूप चीन जन. गण. से पाटन और अधिक नहीं होगा।
- X. पाटनरोधी शुल्क निरस्त करने की स्थिति में, इस उत्पाद को और अधिक पाटित किए जाने तथा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

49. किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

50. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों की अंतिम समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात का निर्धारण करे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखना आवश्यक है। इससे इस बात की भी जांच की अपेक्षा है कि क्या लगाये गये शुल्क से हानिकर पाटन को समाप्त करने के निहित उद्देश्य सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान जांच में चूंकि सतत पाटित आयात हुआ है, प्राधिकारी से इस बात की जांच करने की अपेक्षा नहीं है कि क्या शुल्क को हटाने जाने से संभवतः इस उत्पाद का सतत पाटन होगा। हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मूल और वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और यह कि जहां तक संबद्ध वस्तुओं की मांग और मूल्य का संबंध है, भारतीय बाजार में अनुकूल बाजार परिस्थितियां हैं। प्राधिकारी के पास इस बात पर विश्वास करने का कोई तर्क नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो पाटन और अधिक हो सकता है। यह सच है कि लागू पाटनरोधी उपायों के बावजूद संबद्ध देश अभी भी भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर सकते हैं। निम्नलिखित विश्लेषण सतत पाटन और उसके और अधिक होने की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क के हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान की संभावना को दर्शायेगा।

(i) तीसरे देश को निर्यात के संबंध में पाटन मार्जिन, मूल्य में कटौती और क्षति का मार्जिन

51. आवेदक ने भी यह दर्शाते हुए सूचना प्रदान की है कि चीन से तीसरे देशों को निर्यात सामान्य मूल्य से बहुत कम कीमत पर किया जा रहा है। आवेदक ने तीसरे देश को निर्यात की गई वस्तु के मूल्य पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन, हानि का मार्जिन और मूल्य में कटौती का ब्यौरा प्रदान किया है।
52. प्राधिकारी ने भी पाटन मार्जिन और हानि के मार्जिन का निर्धारण किया है। यदि चीन से आयात उस मूल्य पर किया जाना था जिस पर चीन ने विभिन्न तीसरे देशों को निर्यात किया था। नीचे दी गई तालिका से यह नोट किया जा सकता है कि पाटन मार्जिन और हानि का मार्जिन दोनों बहुत अधिक है।

तीसरा देश विश्लेषण

विवरण	इकाई	पी ओ आई
सामान्य मूल्य	अमरीकी डॉलर/ कि. ग्रा.	***
निबल निर्यात मूल्य	अमरीकी डॉलर/ कि. ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	अमरीकी डॉलर/ कि. ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन रेंज	%	75-85

तीसरे देश का विश्लेषण

विवरण	इकाई	पी ओ आई
क्षति रहित मूल्य	अमरीकी डॉलर/कि. ग्रा.	***
पहुंच मूल्य (तीसरे देश के लिए रिपोर्ट किया गया)	अमरीकी डॉलर/कि. ग्रा.	***
क्षति का मार्जिन	अमरीकी डॉलर/कि. ग्रा.	***
क्षति का मार्जिन	%	***
क्षति के मार्जिन का रेंज	%	60-70

(ii) वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

53. मौलिक प्रथम निर्णायक समीक्षा तथा वर्तमान जांच दोनों में पाटन के मार्जिन का स्तर अधिक है। देश में अधिक मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। इसके अलावा, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात अभी भी पाटित मूल्यों पर किया जाना जारी है। मूल्य में कटौती, कम मूल्य पर बिक्री और मूल्य पर दबाव के स्तर को देखते हुए तथा चीन में क्षमता और भारत में मांग पर विचार करते हुए, पाटित आयात की मात्रा पाटन रोधी शुल्क के हटाये जाने की स्थिति में और अधिक बढ़ने की संभावना है।

(iii) भारतीय बाजार के मूल्य का आकर्षण

54. जिस मूल्य पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात चीन जन. गण. द्वारा भारत को किया जा रहा है वह पाटन के लगातार होने/और अधिक होने की संभावना का एक संकेत है। भारत में वर्तमान पहुंच मूल्य पर जांच की अवधि के दौरान मूल्य में कोई कटौती नहीं हुई है। आवेदक ने यह सूचना प्रदान की है कि जो यह दर्शाता है कि चीन से तीसरे देशों में निर्यात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से बहुत अधिक कम मूल्य पर होता है। इस कारण से यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने के साथ, भारतीय मूल्य चीन के उत्पादकों के लिए इतना आकर्षक हो जायेगा कि वह भारत को अपना निर्यात पाटित मूल्य पर और अधिक नहीं कर पायेगा और इसकी भी बहुत अधिक संभावना है कि भारत के उपभोक्ता चीन से संबद्ध वस्तुओं के व्यापक आयात का मार्ग अपनायेंगे।

(iv) चीन के उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण

55. उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट है कि चीन के उत्पादक/निर्यातक बहुत अधिक निर्यातोन्मुख हैं। उच्च मांग और भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए बाजार की अनुकूल स्थितियों तथा चीन के उत्पादकों की उच्च उत्पादन क्षमता और निर्यात उन्मुखीकरण पर विचार करते

हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को हटा लिया जाता है तब भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग को चीन के उत्पादकों द्वारा पूरा किया जा सकता है।

(V) चीन में उत्पादन की विशाल क्षमता

56. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के पास भारतीय मांग की तुलना में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क के हटाये जाने की स्थिति में और चीन के निर्यातोंन्मुखीकरण पर विचार करते हुए चीन में उत्पादक संबद्ध वस्तुओं में लगे हुए भारत के विनिर्माण क्षेत्र से आगे बढ़ने में सक्षम हैं।

ज. क्षति का आकार और क्षति का मार्जिन

57. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के संबंध में यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के क्षतिरहित मूल्य की तुलना जांच की अवधि के दौरान हानि के मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यात के पहुंच मूल्य से तुलना की गई है और क्षति का प्रस्तावित मार्जिन इस प्रकार नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	पी ओ आई
क्षतिरहित मूल्य	रु./किग्रा.	***
पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	***
क्षति का मार्जिन	रु./किग्रा.	***
हानि के मार्जिन का प्रतिशत	%	***
हानि के मार्जिन का रेंज	%	0-10

58. यह नोट किया जाता है कि जैसा कि ऊपर में दिया गया है हानि के मार्जिन के स्तर को बहुत अधिक माना गया है।

झ. भारतीय बाजार के हित एवं अन्य मुद्दे

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की गलत व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई हानि को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में स्वतंत्र और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से आयात में रुकावट नहीं आयेगी और इसलिए यह उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
60. यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करने वाले विनिर्मित उत्पाद के मूल्य स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप में इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को पाटनरोधी उपायों द्वारा विशेषकर पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से बचाने के लिए एक आवश्यक राशि तक सीमित रखने पर कम नहीं किया जायेगा। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करना दूर किया जायेगा, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में रुकावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक पसंद की उपलब्धता को बनाये रखने में मदद मिलेगी।

ञ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद प्रस्तुत विवरण

61. घरेलू उद्योग ने अपने दावों और प्रस्तुतियों को दोहराया है। घरेलू उद्योग के विचार संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-
- (क) क्षति रहित कीमत पाटनरोधी नियमों के अनुरूप पुनः निर्धारित की जाए।
- (ख) विचाराधीन उत्पाद अपने सामान्य मूल्य से नीचे भारत को निर्यात किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देश से पाटन हो रहा है।
- (ग) वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन दोनों वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के लिए अपेक्षित पाटनरोधी शुल्क संरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजन से तीसरे देशों में पाटन के आधार पर माना जाए।
- (घ) घरेलू उद्योग को उपायों के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पुनः क्षति पहुंची है।
- (ङ.) पाटनरोधी शुल्क तीसरे देशों के लिए निर्धारित क्षति तथा पाटन के आधार पर निर्धारित की जानी अपेक्षित है।
- (च) पाटनरोधी शुल्क निर्धारित रूप में संशोधित किए जाने की आवश्यकता है और शुल्क अमरीकी डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किए जाने की अपेक्षा है।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच

62. घरेलू उद्योग के लिए निबल आयात कीमत पाटनरोधी शुल्कों के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों के संदर्भ में निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग ने तीसरे देशों के निर्यात के आधार पर लाभ के अपने दावों के लिए चीनी सीमाशुल्क के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। तथापि प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तीसरे देश के आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि इसका सत्यापन नहीं किया जा

सकता। क्षति की निरंतरता उपर्युक्त पैराग्राफों में सिद्ध कर दी गई है और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में पाटन एवं मंजूरी की संभावना संबंधी तथ्य भी उपर्युक्त पैराग्राफों में सिद्ध कर दिया गया है। साथ ही यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क जो पिछले 10 वर्षों से लागू है से संबद्ध देश द्वारा वस्तुओं के पाटन के क्षतिकारक प्रभाव नहीं रूक पाए हैं और इसीलिए यह सिफारिश की जाती है कि बैंच मार्के की बजाए पाटनरोधी शुल्क के निर्धारित रूप में शुल्क लगाया जाए।

ठ. निष्कर्ष

63. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध और उसमें उठाये गये मुद्दे की जांच करने के बाद तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत को संबद्ध देश से इसके संबंधित सामान्य मूल्य पर किया गया है और इस प्रकार इस उत्पाद का पाटन हुआ है। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के संबंध में बहुत अधिक हानि हुई है। बहुत अधिक हानि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ड. सिफारिशें

64. यह नोट किया जाता है कि यह जांच शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, हानि और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये थे। पाटन, हानि और उसके पाटनरोधी नियमावली के संबंध में कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने तथा इस प्रकार से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई सकारात्मक पाटन मार्जिन और अत्यधिक हानि को सिद्ध करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और उससे होने वाली हानि से बचने के लिए अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि नीचे दिये गये निर्धारित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।
65. प्राधिकारी द्वारा अपनाये जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और हानि मार्जिन में से जो भी कम है उसके बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	निर्दिष्ट	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2936 28 00 2309 90 10	प्राकृतिक रूप को छोड़कर किसी भी रूप में विटामिन ई	100% ग्रेड	चीन जन.गण	चीन जन.गण.	कोई	कोई	1.77	KG	USD
2.	2936 28 00 2309 90 10	प्राकृतिक रूप को छोड़कर किसी भी रूप में विटामिन ई	100% ग्रेड	चीन जन.गण	चीन जन.गण. से इतर कोई देश	कोई	कोई	1.77	KG	USD
3.	2936 28 00 2309 90 10	प्राकृतिक रूप को छोड़कर किसी भी रूप में विटामिन ई	100% ग्रेड	चीन जन.गणसे इतर कोई देश		कोई	कोई	1.77	KG	USD

नोट:- उपर्युक्त कॉलम (9) के प्रयोजन के लिए धनराशि कॉलम (4) में निर्दिष्ट को छोड़कर संकेन्द्रण के लिए सानुपातिक आधार पर परिकलित की जाएगी।

66. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्क को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।
67. इन परिणामों से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क अधिनियम के अनुरूप सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधीकरण के समक्ष की जा सकेगी।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March 2015

(Final Finding)

Subject: - Final Findings in the Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin E originating in or exported from China PR-reg.

F. No.15/31/2013-DGAD.-1.—Whereas, the original investigation concerning imports of Vitamin E (herein after referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), was initiated by the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) vide Notification No. 14/32/2002-DGAD dated 27th August, 2002. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/32/2002-DGAD dated 2nd December, 2002 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 41/2003-Customs on 7th March 2003. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/32/2002-DGAD dated 22nd August, 2003; recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 145/2003-Customs dated 6th October, 2003 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2. Whereas, the Designated Authority (DA) had initiated first sunset review vide notification No. 15/10/2008-DGAD dated 7th March, 2008. The final finding with respect to the said first sunset review, was notified by the Authority vide Notification No. 15/10/2008-DGAD dated 5th March, 2009. On the basis of this recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No.33/2009–Customs dated 27th March, 2009 and made the antidumping duty effective for a period of five years.
3. Whereas, Merck Limited have filed a duly substantiated application on behalf of the domestic industry before the Authority and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated second sunset review investigation vide Notification dated 24th March, 2014 to review the need for continued imposition of the anti dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 26th March, 2015 vide Notification No.16/2014-Customs (ADD) dated 9th May, 2014.

A. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - (a) The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2) of Customs Tariff Rules, 1995
 - (b) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - (c) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known producers/exporters in China PR (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):
 - (i) M/s. Zhejiang Nhu Company Limited
 - (ii) M/s. Zheijiang Xinchang Pharmaceuticals Company
 - (iii) M/s. Hangzhou Toyond Biotech Co. Ltd.
 - (iv) M/s. Vega Pharma Limited
 - (v) M/s. Xi'an Rainbow Biotech Co. Ltd.
 - (vi) M/s. Qingdao Sunrise Trading Co. Ltd.
 - (vii) M/s. Anhui Medifarm Co. Ltd.
 - (d) No response or submission has been filed by any of the producers/exporters from the subject country.
 - (e) A Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to all the known producers/exporters and the Embassy of China PR with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time. While for the purpose of initiation the Normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers

of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers. However, no response has been received from any of the producers/exporters of China PR in this regard.

- (f) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):
 - (i) M/s C.J Shah & Co., Mumbai
 - (ii) M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd., Ahmedabad.
 - (iii) Glenmark Pharmaceuticals Ltd., Mumbai.
 - (iv) Medi Pharma Drug House, Mumbai.
 - (v) Nandlal Bankatlal Pvt. Ltd., Mumbai.
 - (vi) Nav Maharashtra Chakan Oil Mills, Pune.
 - (vii) M/s Sheetal Pharma., Mumbai.
 - (viii) Sundar Chemicals Pvt. Ltd., Chennai.
 - (ix) Universal Medicare Pvt. Ltd., Mumbai
- (g) No response or submission has been filed by any of the importers/users/associations or any other interested parties.
- (h) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review was 1st January, 2013 to 31st December, 2013. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods January-December 2010, January-December 2011, January-December 2012 and the POI.
- (i) The domestic industry had relied upon the data from the secondary sources i.e. IBIS. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period including the POI and also the post-POI. Since during the POI the volume of the imports of the subject goods from the subject country, is higher as per the IBIS source, the Authority has relied upon the data from the IBIS source in the present investigation.
- (j) Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating parties by the Authority.
- (k) The Authority had made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7) of Custom Tariff Rules, 1995.
- (l) The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- (m) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th January, 2015, which was attended only by the domestic industry and their representatives. The domestic industry which only presented its views in the oral hearing was requested to file written submissions of the views expressed orally.
- (n) The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority have been examined and addressed in this investigation.
- (o) Verification of the information and data submitted by the interested parties was carried out to the extent deemed necessary.
- (p) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- (q) Wherever, an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these essential facts on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.
- (r) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 10.03.2015. The post Disclosure Statement submissions were received from the Domestic Industry only and have been considered, to the extent found relevant in this Final Findings Notification.
- (s) The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been addressed in this Final Findings Notification.

- (o) ***in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (p) The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.58.95 = 1 US\$.

B. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product under consideration (PUC) in the previous investigations as well as the present Sunset Review investigation is “Vitamin-E in all forms, excluding natural forms”, originating in or exported from China PR. The present investigation being a 2nd sunset review, the investigation covers the product as in the original and subsequent sunset review investigations. Vitamin E Acetate is the stable form of Vitamin E, most often used in cosmetic formulations for its skin care benefits. Vitamin E protects cell membranes from damage by oxygen free radicals. It can prevent premature aging of the skin induced by UV irradiation and lipid peroxidation. Whereas, Vitamin E feed grade is used in the preparations for animal feed.
6. The Authority notes that none of the interested parties has contested the meaning and scope of the product under consideration as defined by the Authority. The Authority further notes from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the previous two investigations, which is relied upon. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable.
7. The product, Vitamin E-Acetate is classified in Chapter 29 under Customs Classification 2936 28 00 of the Customs Tariff Act whereas Vitamin-E (50% dry powder) feed grade is classified in Chapter 23 under Customs Classification 2309 90 10. However, the above classification is indicative only and is no way binding on the investigation.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by the Domestic Industry

8. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
 - (i) The petition has been filed by M/s. Merck Ltd. Another company M/s. Soham Organics Ltd., Nashik also produces the product. The other manufacturer has no objection to the petition though they have not submitted any letter to that effect.
 - (ii) The petitioner has 84% share in the Indian production during the POI and, therefore, constitutes domestic industry. Further, the scope of domestic industry and standing are not relevant in a sunset review.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

9. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

Examination by Authority

10. The Authority notes that the application in the present Sunset Review investigation has been filed by M/s Merck Ltd. as the domestic industry.
11. The Authority further notes that M/s Soham Organics also produces the product. As per the information provided by the domestic industry, M/s Merck Ltd commands 84% share in Indian production in the POI. The production of the applicant constitutes major portion of the total production of the subject goods and, therefore, applicant constitutes the domestic industry. Moreover, as regards the standing and scope of domestic industry, there is no opposition from any interested party in the present investigation. In view of the above position and having regard to the Rules and information on record, the Authority holds that M/s Merck Ltd., accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules and has standing under the Rules.

D. Market Economy Treatment, Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin—Methodology, Parameters and Likelihood of Continuation of Dumping.

Submissions by the Domestic Industry

12. Following are the submissions made by the domestic industry:
 - i. Since no questionnaire response has been filed by any of the Chinese companies, the subject country should be treated as non-market economy.
 - ii. In the previous sunset review investigations, the Authority had not granted market economy treatment to any of the exporters from China and determined the normal value in China on the basis of the constructed normal value based on the estimated cost of production of the subject goods in China with reasonable profit in terms of Para 7

- & 8 of the Annexure 1 to the said Rules as amended. Authority should consider the same methodology to calculate the normal value for China PR in the current investigation.
- iii. The Normal value in China can be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. Normal Value in China should be determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted.
 - iv. The petitioner has claimed consideration of the same methodology to calculate the normal value for China PR in the current investigation also as none of the exporters/producers from China have responded to the initiation of investigation.
 - v. The petitioner considered IBIS data to assess the volume and value of subject import in India. However, the price reported to Indian customs is unreliable. This is established by the fact that the price at which Vitamin-E has been exported from China to the rest of the world is materially lower than the price at which the goods have been exported to India. The prices at which the goods have been reported in Indian customs are at the prevailing benchmark price for the product in India. The price at which the imported goods have been resold in India, as evidenced by the resale price of the product, is materially lower.
 - vi. In view of the above, petitioner requests the Designated Authority to ignore the prices reported to Indian customs and considers the resale price of the product for constructing the import price. Petitioner requests the Designated Authority to kindly consider the definition of the export price under the law. In the present case, since the price at which the goods have been exported is unreliable, the export price is required to be constructed from the resale price in India.
 - vii. It would be seen from calculations of dumping and injury margin on the basis of country-wise exports from China as per China Customs data that exports from China to third countries are at dumped prices. It would be seen that the dumping margin and injury margin in respect of majority of the countries is quite significant.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

13. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

Examination of Market Economy Claims

14. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. In view of the above position, the Authority treats the subject country as non-market economy in the present investigation.

Determination of Normal Value

15. The Authority notes that none of the producers and exporters of the subject goods from the subject country has submitted the exporter's questionnaire response and market economy questionnaire response, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. In view of the above position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption by the respondent Chinese company, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Ann.I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
16. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:
"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the Designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."
17. None of the exporters/producers from the subject country has cooperated with the Authority and responded to the present investigation. Further none of the interested parties has provided any other alternate basis as defined in the

Rules on which normal value can be determined. In view of the above position and considering China as a non-market economy, the Authority has determined the normal value in accordance with Para 7 of Annexure I of the AD Rules. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the Authority has determined the normal value by adopting the method of “other reasonable basis”. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of the best estimates of cost of production of the applicant domestic industry in India. The Authority has also provided for reasonable profit as per its consistent practice. Accordingly, the constructed normal value for Chinese exporters as determined is given in the dumping margin table below.

Export Price

18. None of the exporters in the subject country has provided any information that can be used for determination of the export price. The applicant has claimed that the prices declared in Bill of Entry to Indian customs is unreliable because of the benchmark form of anti dumping duty imposed on the product. They are alleging it on the grounds that the price at which Vitamin-E has been exported from China to rest of the world is materially lower than the price at which the goods have been exported to India. The subject goods have been exported to India nearly at the prevailing benchmark price for the product as notified in earlier ADD Notification. The applicant has submitted one resale invoice relating to post-POI period, wherein the price is lower than the import price, thereby supporting their claim that prices declared to Customs are incorrect and is just to avoid payment of customs duty under ADD notification.
19. The Authority considers it inappropriate to determine export price on the basis of reported resale price in India. Also the goods are coming into India at approximately the same price from all the countries. None of the exporters from China have cooperated with the Authority and therefore export price cannot be determined on the basis of questionnaire response. The Authority has determined the export price for all exporters from China PR on the basis of IBIS import information. These prices are CIF export price to India. The adjustments from the CIF prices have been made as per facts available on record. Accordingly, the export price has been adjusted for commission, port expenses, bank charges, inland, sea freight and marine insurance. The Net Export Price worked out by the Authority is given in the dumping margin table below.

Dumping Margins

20. Comparing the constructed normal value with the export price at ex-factory level as determined above, the dumping margin for all the producers/exporters in the subject country is determined as follows:-

Normal value	US\$/Kg	***
Net Export price	US\$/Kg	***
Dumping Margin	US\$/Kg	***
Dumping Margin percentage	%	***
Dumping Margin Range	%	5-15

E. Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link

Submissions by the domestic industry

21. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:
 - i. There is continued dumping of the product under consideration from China.
 - ii. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty cease.
 - iii. Volume of dumped imports has increased in spite of current anti-dumping duties.
 - iv. Price undercutting is significantly positive. Further, Chinese exporters are dumping the product to various other countries in significant volumes as is evident from the price undercutting determined for the major importing countries.
 - v. Performance of the domestic industry in terms of profits, return on investments, inventories etc. has deteriorated in the current Period of Investigation.
 - vi. Even though performance of the domestic industry improved on account of production, sales and capacity utilization; the performance of the domestic industry was clearly sub-optimal despite anti dumping duty imposed, as is clearly established by the past levels of capacity utilization of the domestic industry and suspension of production by the domestic industry in the post-POI period.
 - vii. Despite anti dumping duty in force, the price parameters of the Domestic Industry have declined. Should the current anti dumping duties cease, the Domestic Industry would be forced to sell its product at a price comparable to import prices. This would mean significant financial losses, negative return on investment and significant cash losses.
 - viii. Following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports and thereby establish causal link:

- (a) The dumped imports from the subject country have continued to enter the Indian port in the period of investigation.
- (b) Subject imports are available at prices lower than domestic prices. Once anti-dumping duty is discontinued, the dumped imports will cause further injury.
- (c) Imports of the product under consideration have increased over the injury period. Consequently, the market share of the domestic industry has declined.
- (d) The capacities available with the Chinese producers and their export orientation suggest that in case anti dumping duty is discontinued; the volume of dumped imports would surge further.
- (e) The imports are entering the country at low and dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry would, therefore, be forced to reduce the prices in the event of cessation of anti dumping duty.
- (f) The imports are undercutting the domestic prices. Resultantly, the domestic industry is already faced with price depression in the market. This has resulted in financial losses to the domestic industry, which would increase further in the event of cessation of anti dumping duty.
- (g) Performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits, return on investment and cash flow as a result of price depression.
- (h) In the absence of an anti dumping measure, the likelihood of continuation of dumping and injury cannot be ruled out.
- (i) Calculations of dumping and injury margin in respect of exports from China to all third countries to which China has exported, including dumping margin and injury margin on the basis of weighted average export price show that the dumping margin and injury margin in respect of majority of the countries are significant.

Submissions by producers/exporters/importers other interested parties

22. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions with regard to injury to the domestic industry.

Examination by the Authority

23. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
24. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
25. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
26. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
27. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Merck Ltd., constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

VOLUME EFFECT**Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry****Demand and Market Share**

28. The demand and market share are analyzed as below:

Particulars	Unit	2010	2011	2012	POI
Assessed Demand	MT	837	980	1,071	1,377
Sales of Domestic industry (including captive consumption)	MT	316	370	438	461
Sales of Other Producers	MT	100	100	100	100
Imports—China PR	MT	49	105	243	253
Imports—Other countries	MT	372	405	289	562
Market share in demand					
Domestic Industry	%	38	38	41	34
Other Indian Producers	%	12	10	9	7
Subject country-Imports	%	6	11	23	18
Other Countries-Imports	%	44	41	27	41

29. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the country as the sum of domestic sales of the Indian producers (the sale of other producer is an estimated figure by the petitioner) and imports from all sources as available from IBIS. The petitioner has claimed import volumes from China to be considered on the basis of exports to India from China as per China Customs, as submitted by the petitioner. However, the Authority has considered injury analysis based on IBIS import data. Based on this, the demand has been assessed, as mentioned in the above table. The Authority notes that demand for the product in the country during POI increased vis-à-vis the base year as well as the immediate preceding year.
30. The Authority further notes that the market share of the domestic industry has declined during the POI as compared to the base year as well as the immediate preceding year. On the contrary, the share of imports from the subject country has increased during the POI as compared to the base year.

Import Volume & market share

31. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2010	2011	2012	POI
Subject Country	MT	49	105	243	253
<i>Trend</i>	Indexed	100	212	493	513
Other Countries	MT	372	405	289	562
<i>Trend</i>		100	109	78	151
Total Imports	MT	421	510	533	816
Demand	MT	837	980	1071	1377
Domestic production	MT	360	426	466	508
Market share of imports from subject country in relation to					
Total Imports	%	12%	21%	46%	31%
Demand	%	6%	11%	23%	18%
Domestic Production	%	14%	25%	52%	50%

32. The Authority notes that the volume of imports from the subject country on this basis is significant in absolute terms. Further, the imports from the subject country vis-à-vis domestic demand and production have also increased during the POI as compared to the base year.

PRICE EFFECT

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

33. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of the principles outlined in Annexure-III to the Rules by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The landed value of subject imports has been considered on the basis of export price based on IBIS import data. The position is as follows:

Particulars	Unit	2010	2011	2012	2013
Import Volume	MT	49	105	243	253
Import Value	Rs. Lacs	736	1419	3439	3596
Landed price of imports	Rs./Kg	***	***	***	***
Net Selling Price of DI (Avg.)	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting Range	%	10-20	0-10	0-10	(0-10)

34. It is noted from the table above that there is no price undercutting in the POI, even though the price undercutting was positive in previous years. The applicant has claimed that exports from China to third countries show significant price undercutting and price underselling on weighted average basis as well as in majority of the third countries. The applicant has provided details of reported price undercutting and price underselling considering the price at which goods have been exported by China to various third countries which shows that both the price undercutting and price underselling are quite significant.

Price Underselling

Particulars	Unit	POI
Non injurious Price	Rs./KG	***
Landed Value	Rs./KG	***
Price Underselling	Rs./KG	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling Range	%	0-10

35. It is noted that the landed price of imports of subject goods from the subject country is below the non-injurious price of the domestic industry, resulting in price underselling.

Price Suppression and Depression

36. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales. The data given in table below shows that the cost of sales of the domestic industry has declined in 2011, remained at the same level in 2012 and then increased significantly in the POI. On the other hand, the selling price has declined over the injury

period, resulting in significant losses to the domestic industry in the POI. This shows that the domestic industry was affected by price depressing and suppressing effects of dumped imports from the subject country.

Particulars	Unit	2010	2011	2012	POI
Cost of sales	Rs./Kg	1,393	1,357	1,358	1,679
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>120</i>
Selling price	Rs./Kg	1,851	1,526	1,539	1,480
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>83</i>	<i>80</i>
Landed price of imports	Rs./Kg	1,591	1,444	1,508	1,514
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>91</i>	<i>95</i>	<i>95</i>

Examination of other economic parameters of the domestic industry

37. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Sales, Capacity, Production, Capacity Utilization and Inventories

38. The Authority notes from the table below that there is no change in the capacity for the product under consideration. Production and sales volume of the domestic industry have increased over the injury period. The capacity utilization has also improved as a result of increase in production due to outsourcing. The petitioner has claimed that the capacity is still under-utilized. This is in spite of the fact that the demand in the country is significantly higher than the petitioner's capacity. The petitioner has further claimed that they were forced to curtail and even suspend production in the post-POI period due to significant rise in inventories. This shows that increase in domestic sales is not proportionate to the increase in production which is leading to piling up of stock.

Particulars	Unit	2010	2011	2012	POI
Capacity	MT	600	600	600	600
Production	MT	360	426	466	508
Capacity Utilization	%	60	71	78	85
Domestic Sales	MT	175	242	273	326
Captive transfer	MT	141	129	165	135
Average Inventories	MT	16	12	7	32

Profit/loss, return on investment and cash flow

39. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Particulars	Unit	2010	2011	2012	POI
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>120</i>
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>83</i>	<i>80</i>
Profit/loss	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>37</i>	<i>40</i>	<i>-43</i>
Profit/loss (total)	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>51</i>	<i>62</i>	<i>-81</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>54</i>	<i>65</i>	<i>-75</i>
Return on Capital employed	%	***	***	***	***

40. The Authority notes that the cost of sales has declined in 2011, remained at the same level in 2012 and then increased significantly in the POI. The reason for increase in cost mentioned by the DI is that there is significant increase in price of one of the raw material namely Isophytol. However, the selling price has declined over the

injury period, resulting in significant losses to the domestic industry. It is also noted that the domestic industry has incurred losses during the POI. Further, return on investment was significantly negative in the POI. The petitioner has claimed that the imports are depressing the domestic prices, leading to deterioration in profitability of the domestic industry.

Market Share

41. The data given in the table below shows that the market share of domestic producers has declined; whereas market share of imports from the subject country has increased with reference to the preceding year.

Market share in Demand	Unit	2010	2011	2012	POI
Domestic Industry	%	38	38	41	34
Other Indian Producers	%	12	10	9	7
Subject country-Imports	%	6	11	23	18
Other Countries-Imports	%	44	41	27	41

Employment and wages

42. From the table given below, the Authority notes that both the employment and wages of the domestic industry has increased during the POI as compared to the base year. It is, however, noted that the petitioner being multi-product company, these parameters may not show current and potential adverse impact.

Particulars	Unit	2010	2011	2012	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>132</i>	<i>174</i>	<i>211</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>86</i>	<i>102</i>	<i>159</i>

Productivity

43. The Authority notes from the table below that productivity per day of the domestic industry during POI has increased as compared to the base year. However, the productivity per employee shows a decline as the number of employees has increased. This could also be one of the factors for increased costs.

Particulars	Unit	2010	2011	2012	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>130</i>	<i>141</i>
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>74</i>	<i>67</i>

Magnitude of Dumping Margin

44. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive.

Growth

45. The Authority notes that the domestic industry has shown positive growth in some of the economic parameters such as production and domestic sales. However, price parameters such as profit, cash profit and return on investments have deteriorated during the POI as compared to the base year.

Growth year by year	Unit	2010	2011	2012	POI
Production	%	-	18.07	9.53	8.91
Sales Volume	%	-	37.81	13.06	19.42
Cost of Production	%	-	-2.59	0.06	23.64
Selling Price	%	-	-17.55	0.87	-3.85
Return on Capital Employed	%	-	-55	9	-230

Ability to raise Capital Investment

46. Since the domestic industry is a multi-product company, its ability to raise capital investment has not been affected due to dumping of the subject goods from the subject country.

F. Causal Link

47. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry.
- Imports from Third Countries:** - The Authority notes that imports of product under consideration from other countries are significant in volume. The applicant has submitted that imports from third countries are at a price slightly higher than the import price from China. It has been claimed that the exporters from third countries are being forced to sell at the prices offered by Chinese exporters so as to compete with them. The Authority notes from the information available on record that the claimed injury cannot be attributed to imports from third countries.
 - Contraction in Demand:** - The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has consistently increased over the injury period.
 - Pattern of consumption:** - It is noted that no significant change in the pattern of consumption for the subject goods has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission in that regard.
 - Conditions of competition:** - The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.
 - Developments in technology:** - The Authority also notes from the information available on record that the investigation has not shown that the claimed injury could be due to change in technology.
 - Export performance of the domestic industry:** - The export performance of the domestic industry is not relevant since the price and profitability of the domestic industry has been segregated by the Authority for domestic and export markets separately for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

G. Likelihood of dumping and injury

Submissions by the domestic industry

48. Following are the submissions made by the domestic industry:
- Exporters in the subject country have capacities far in excess of Indian demand. In case of revocation of anti-dumping duty, the volume of subject goods' imports is bound to increase further.
 - Production capacity available with some of the Chinese producers are as below, while the actual production capacity in the country may be in the range of 55000 to 60000 MT per annum (obtained from online sources):

S. No.	Name of the Producer	Annual Production Capacity (MT)
1	Hangzhou Toyond Biotech Ltd.	15,000–40,000
2	Zhejiang Medicine Co. Ltd.	20,000

- The exporters from China PR have very high export orientation worldwide. The export percentage of the Chinese companies varies from 81-100% (obtained from online sources):

Producer/exporter	Export Orientation
Vega Pharma Limited	81%–90%
Xi'an Rainbow Biotech Co. Ltd.	81% - 90%
Qingdao Sunrise Trading Co. Ltd.,	91% - 100%
Anhui Medifarm Co. Ltd.,	91% - 100%

- iv. Majority of the producers of the product under consideration in China producing Vitamin E are state owned/controlled enterprises. Chinese Government has major stake in shares or they control the management. The objective of these companies is therefore only somehow getting business and not the prices at which they would sell the product. It would be seen that about 80% of exports of the product under consideration from China are by state owned/controlled entities.
- v. Dumping margins in the previous two investigations were significantly high.
- vi. The performance of the domestic industry was sub-optimal despite anti dumping duty was in force.
- vii. Imports from the subject country would undercut the prices of the domestic industry in the Indian market in the absence of anti-dumping duty.
- viii. The landed price of imports is substantially below the cost and selling price of the domestic industry. Thus, in the event of cessation of current anti-dumping duty and if the domestic industry chooses to sell at the import prices, the domestic industry would suffer significant financial losses.
- ix. The exporters and producers from the subject country have continued to export the material at the dumped prices even after the imposition of the anti-dumping duty. There is no reason to consider that revocation of duties in the present case would not result in intensified dumping from China PR.
- x. In the event of revocation of the anti-dumping duty, the product is likely to be dumped more intensively and undercut the prices of the domestic industry.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

49. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

Examination by the Authority

50. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination as to whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In the present investigation, as there are continued dumped imports, the Authority is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product. However, considering the fact that the dumping margin in the original as well as the present investigation is positive and that there are favorable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reason to believe that dumping may intensify if the anti dumping duty is revoked. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject country could still dump the subject goods in the Indian market. The following analysis would show about the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty:

(I) Dumping margin, price undercutting and injury margin in respect of exports to third countries

51. The applicant has also provided information showing that exports from China to third countries are at prices materially below the normal value. The petitioner has provided details of dumping margin, injury margin and price undercutting considering the price at which goods have been exported to third countries.
52. The Authority has also determined dumping margin and injury margin if the imports from China were to be made at prices at which China had exported to various third countries based on the data provided by the Domestic Industry. It may be noted from the Table given below that both the dumping margin and injury margin are quite significant.

Third Country Analysis

Particulars	Unit	POI
Normal Value	US\$/KG	***
Net Export Price	US\$/KG	***
Dumping margin	US\$/KG	***
Dumping margin	%	***
Dumping margin Range	%	75-85

Third Country Analysis

Particulars	Unit	POI
Non injurious Price	US\$/KG	***
Landed Value (<i>reported for 3rd country</i>)	US\$/KG	***
Injury margin	US\$/KG	***
Injury margin	%	***
Injury margin Range	%	60-70

(i) Level of current and past dumping margin

53. The level of dumping margin both in the original, first sunset review as well as present investigation is significant. Despite significant demand in the country, the domestic industry could not utilize its full capacity. Further, the import of the subject goods from the subject country still continues to be at dumped prices. Given the level of price undercutting, price underselling and price depression and considering the capacity in China and demand in India, the volume of dumped import is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

(ii) Price attractiveness of Indian market

54. The price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the current landed price in India, there is no price undercutting during POI. The applicant has provided information which shows that exports from China to third countries are at prices materially below the selling price of the domestic industry. It is therefore noted that, with the revocation of anti-dumping duty, the Indian prices would be too attractive for the Chinese producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from China..

(iii) Export orientation of Chinese producers

55. From the available information it is evident that the Chinese producers /exporters are very much export oriented. Considering the high demand and favorable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of the Chinese producers, the Authority holds that if the existing antidumping duties are withdrawn, the entire demand for the subject goods in India can be catered by the Chinese producers.

(iv) Huge Production Capacity in China

56. As per the information furnished by the domestic industry, the producers of the subject goods in China hold production capacity of the subject goods far more than Indian demand. In the event of revocation of anti-dumping duty and considering the Chinese export orientation, the producers in China are capable of overtaking the Indian manufacturing sector engaged in subject goods.

H. Magnitude of Injury and injury margin

57. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Particulars	Unit	POI
Non injurious Price	Rs/kg	***
Landed Value	Rs/kg	***
Injury margin	Rs/kg	***
Injury margin Percentage	%	***
Injury margin Range	%	0-10

58. It is noted that the level of injury margin, as above, is considered significant.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES:

59. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

60. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

K. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

61. The Domestic industry as repeated their claims and submissions. The views of the Domestic Industry in brief are as below:
- Non-injurious price may be re-determined confirming to AD Rules.
 - Product under consideration continues to be exported to India below its normal value resulting in dumping from the subject country.
 - Both dumping margin and injury margin in the current Period of Investigation may be considered on the basis of dumping in third countries for the purpose of determining the quantum of anti dumping duty protection required for the domestic industry in the present case.
 - Domestic Industry has once again suffered injury in spite of existing anti dumping duty due to form of measures.
 - The anti dumping duty is required to be determined on the basis of dumping and injury determined for third countries.
 - The anti dumping duty is required to be modified to fixed form and the duty expressed in US\$ terms.

L. EXAMINATION OF THE POST DISCLOSURE COMMENTS

62. The NIP for the domestic industry has been determined in terms of the principles outlined in Annexure-III to the AD Rules. The Domestic Industry has furnished the data of China Customs for their claims of benefit based on third country exports. However, the Authority is not relying on third country data provided by Domestic Industry as it is not verifiable. The continuity of injury has been established in above paras and the fact of likelihood of dumping and injury in case of removal of anti-dumping duty has also been established in above paras. Further, it is noted that the anti dumping duty which is in force for last ten years has not been able to prevent the injurious effect of dumping of goods by the subject country and therefore it is recommended to impose fixed form of anti dumping duty instead of benchmark.

L. CONCLUSION

63. After examining the submissions made by the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, it is concluded that the product under consideration has been exported to India from the subject country below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

O. RECOMMENDATIONS

64. It is noted that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, it is felt that the imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.
65. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duties as per the amount specified in the table below are recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of exports	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2936 28 00 2309 90 10	Vitamin E in all forms excluding natural form	100% grade	China PR	China PR	Any	Any	1.77	KG	USD
2.	2936 28 00 2309 90 10	Vitamin E in all forms excluding natural form	100% grade	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	1.77	KG	USD
3.	2936 28 00 2309 90 10	Vitamin E in all forms excluding natural form	100% grade	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	1.77	KG	USD

Note: The amount for the purposes of column (9) above, for concentrations other than those specified in column (4) shall be calculated on pro rata basis.

66. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
67. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J K DADOO, Designated Authority